उत्तर उजाला

वर्ष 42 अंक 114 नैनीताल, गुरुवार 14 मार्च, 2019 (फाल्गुन शुक्ल अष्टमी संवत 2075) पृष्ठ 12 डाक पंजी. सं. UA/NTL-26/2018-2020 मूल्य 3.00 रु.

आलिया को मिली राजामौली की फिल्म- 7 ओलंपिक के लिए कोशिश करेंगी दीपा कर्माकर-8

तापमान	आज		कल	संभावित
शहर	अधि.	न्यू.	अधि.	न्यू.
दिल्ली	24	14	25	13
लखनऊ	31	18	31	17
नैनीताल	15	07	15	08
देहरादून	22	13	22	12
बरेली	28	15	29	15

सोना (10 ग्राम)	चांदी (प्र. किग्रा.)
33,385	39,710

रुपये की विनिमय दर	
पाउण्ड	91.94
यूरो	78.63
डालर (यूएस)	69.52
स्विस फ्रेंक	69.19
एमीरट्स-दरहम	18.93

मतदाताओं को जागरूक करें दिग्गज हस्तियां

लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग करें मताधिकार का प्रयोग : मोदी

- प्रधानमंत्री ने राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, कला, खेल और मीडिया जगत की हस्तियों से की अपील
- देश की विकास यात्रा में हमारी भागीदारी का संकल्प है वोट
- मताधिकार का देश की आकांक्षाओं व सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, कला, खेल और मीडिया जगत की हस्तियों से आज अपील की कि वे मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाने में मदद करें, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राकांपा प्रमुख शरद पवार, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन समेत कई नेताओं से अपील की कि वे मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। मोदी ने ट्वीट किया, मैं राहुल गांधी, ममता बनर्जी, पवार, मायावती, अखिलेश यादव, (बिहार में नेता प्रतिपक्ष) तेजस्वी यादव और एमके स्टालिन से अपील करता हूं कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। अधिक मतदान हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी से अपील करता हूं कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों में अधिकतम भारतीयों को लाने के लिए काम करें। मोदी ने एशियन न्यूज इंटरनेशल की संपादक स्मिता प्रकाश और समाचार एजेंसी पीटीआई समेत मीडिया जगत से भी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने में योगदान देने की अपील की।

उन्होंने श्रीश्री रविशंकर समेत आध्यात्मिक जगत के नेताओं, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त, पहलवान सुशील कुमार, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू और सायना नेहवाल समेत खेल जगत की हस्तियों से भी मतदाताओं को जागरूक बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, एआर रहमान, (शेष पृष्ठ 10 पर)

21वीं सदी के युवाओं को वोट करने का अवसर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2019 का चुनाव बहुत ही खास है, क्योंकि 21वीं सदी में जन्म लेने वाले युवाओं को वोट करने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि जिन युवाओं को वोट देने का अधिकार है और जो अब तक खुद को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द ऐसा करेंगे और हमारे महान लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे।

मतदाता सूची में अच्छे से करें अपने नाम की जांच

प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने नाम की जांच मतदाता सूची में अच्छे से कर लें। समय रहते एक बार फिर से मतदाता सूची को देखें और ये जांच लें कि उसमें आपका नाम दर्ज है या नहीं। ये सुनिश्चित करें कि जहां आप रहने गए हैं, वहां की मतदाता सूची में आपका नाम हो। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख तक इंतजार नहीं करें और आज ही अपना नाम जुड़वा लें।

सोच समझकर तय करें कार्यक्रम

प्रधानमंत्री ने लिखा कि अपने कार्यक्रम सोच समझकर तय करें। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आने वाले दिनों की योजना इस तरह बनाएं कि आप मतदान के दिन उपलब्ध हों। आपका एक वोट राष्ट्र का भविष्य तय करेगा, इसलिए जरूरत पड़े तो वोट डालने के लिए छुट्टी भी लें। मोदी ने कहा कि मतदान के लिये दूसरों को भी प्रेरित करें।

प्रत्याशी चयन का एकमात्र आधार जीत की संभावना

प्रत्याशियों के नामों की घोषणा 18 तक

चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटेगी भाजपा : गहलोत

देहरादून। उत्तराखंड के लिये भाजपा के चुनाव प्रभारी थावर चंद गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य में 11 अप्रैल को होने वाले आम चुनावों में प्रत्याशियों का चयन उनके जीतने की संभावना के आधार पर किया जायेगा।

प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख गहलोत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राज्य की पांचों लोकसभा सीटों के लिये प्रत्याशियों के नामों की घोषणा 18 मार्च तक हो जायेगी। गहलोत ने कहा कि 16-18 मार्च के बीच पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय कर दिये जायेंगे, जहां पहले चरण में मतदान होना है। उन्होंने कहा कि 18 मार्च तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जायेगी। उत्तराखंड की सभी पांचों लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है, जिसके लिये 18 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और उसी के साथ नामांकन पत्रों के भरने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी।

यह पूछे जाने पर कि पौड़ी से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भाजपा नेता ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह क्या चाहते हैं। इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि स्वास्थ्य कारणों के चलते शायद खंडूड़ी इस बार चुनाव नहीं लड़ें। देश भर में माहौल भाजपा के पक्ष में होने का दावा करते हुए गहलोत ने कहा कि चुनावों के बाद पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटेगी। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने जनता से किये वायदों को पूरा किया (शेष पृष्ठ 10 पर)

संक्षिप्त

भूस्खलन में 36 से अधिक दुकानें दबीं

भद्रवाह। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में एक ग्रामीण बाजार में बुधवार सुबह भूस्खलन के कारण करीब 36 से अधिक दुकानें दब गईं। भद्रवाह के पुलिस अधीक्षक राज सिंह गौरिया ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भालेसा के भथरी बाजार में हुई। गौरिया तलाश और बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने प्राथमिक तौर पर मिली सूचना के अनुसार बताया कि करीब तीन दर्जन दकानें भूस्खलन के कारण दब गई। घबराए हुए नागरिकों ने बताया कि काफी तेज आवाज सुनकर उनकी आंख खुली।

यात्री वाहनों की बिक्री आठ प्रतिशत गिरी

नयी दिल्ली। वाहन विक्रेताओं के संघ एफएडीए के मुताबिक फरवरी में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 8.25 प्रतिशत घटकर 2,15,276 वाहन रही। फरवरी 2018 में यह आंकड़ा 2,34,632 वाहन का था। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार समीक्षावधि में दोपहिया वाहनों की बिक्री 7.97 प्रतिशत घटकर 11,25,405 इकाई रही, जो इससे पिछले वर्ष में इसी दौरान 12,22,883 वाहन थी। एफएडीए के अध्यक्ष आशीष हर्षराज काले ने एक बयान में कहा कि जनवरी में यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी थी। इसकी वजह साल के आखिरी स्टॉक को खत्म करना और कुछ नए लॉन्च करना हो सकती है, लेकिन फरवरी में इनकी खुदरा बिक्री में फिर गिरावट देखी गई और यह चालू वित्त वर्ष में सबसे धीमी रफ्तार रही है।

जैसलमेर में पाक जासूस गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सामरिक महत्व की सूचना भेजने में संलिप्त एक जासूस को जयपुर सीआईडी की विशेष शाखा ने गिरफ्तार किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया कि जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में हिरासत में लिये गये नवाब खां (36) को सीआईडी विशेष शाखा जयपुर के स्पेशल पुलिस थाना में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

आतंकवादियों ने की पूर्व एसपीओ की हत्या

श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के एक गांव में आतंकवादियों ने पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) की बुधवार को दिन-दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान आशिक अहमद नायक के तौर पर हुई है। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संबद्ध माने जा रहे आतंकवादियों ने पिंगलीना इलाके में नायक पर गोली चला दी। इसी इलाके में 18 फरवरी को मुठभेड़ में तीन आतंकवादियों को मार गिराया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 25 वर्षीय नायक सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इंफैंट्री में शामिल हुआ था, लेकिन प्रशिक्षण का सामना नहीं कर पाने के बाद वह सेना छोड़ चुका था।

कौन रच रहा महाराज के खिलाफ षड्यंत्र!

कांग्रेस में वापसी व चुनाव लड़ने की अटकलें

मैं और मेरे परिवार का कोई सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदार नहीं : महाराज

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून/नई दिल्ली। तो क्या कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? उनकी बढ़ती लोकप्रियता से आखिर किसको खतरा है? उनके कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी-गढ़वाल से चुनाव लड़ने के कयास लगाकर विभिन्न प्रचार माध्यमों तक पहुंचाने वालों का उद्देश्य क्या रहा होगा? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं।

स्वयं महाराज ने बुधवार को दिल्ली में मीडिया के सामने स्थिति साफ की तो उनके विरुद्ध षड्यंत्र का पहलू भी स्पष्ट हो गया। सतपाल महाराज उत्तराखण्ड सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अतीत में उनका कांग्रेस से नाता रहा और वे पौड़ी से सांसद व केन्द्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से उनकी कांग्रेस में वापसी और पौड़ी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों के साथ खबरें फैलाई जा रहीं थी। इस बीच कांग्रेस विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष डा. इन्दिरा हृदयेश का एक बयान आया, जिसमें कहा गया था कि (शेष पृष्ठ 10 पर)

पीओके में पाकिस्तानी फाइटर जेट ने भरी उड़ान

पुंछ। दो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मंगलवार रात सुपरसोनिक गति से उड़ान के दौरान रडार की पकड़ में आये। ये विमान नियंत्रण रेखा से 10 किलोमीटर की दूरी पर पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सीमा में देखे गई, जिसके बाद भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को हाईअलर्ट पर रख दिया। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से इलाके में काफी तेज आवाज सुनाई दी।

गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आत्मघाती बम हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गये थे, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत ने 26 फरवरी को आतंकवाद-रोधी कार्रवाई शुरू करते हुए बालाकोट में अभियान चलाया था।

लीक दस्तावेजों से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में

राफेल मामले में रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा

सिन्हा, शौरी और भूषण संवेदनशील जानकारी लीक करने के दोषी

नयी दिल्ली। केन्द्र ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि राफेल सौदे पर उसके फैसले पर पुनर्विचार के लिये याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये संवेदनशील हैं। जिन लोगों ने इन दस्तावेजों की फोटोकापी बनाने की साजिश की, उन्होंने इसकी चोरी की और इन्हें लीक करके सुरक्षा को खतरे में डाला है।

रक्षा मंत्रालय ने इस हलफनामे में कहा है कि इन संवेदनशील दस्तावेजों के लीक होने की घटना के संबंध में 28 फरवरी को आंतरिक जांच शुरू हुयी जो अभी भी जारी है और यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि ये लीक कहां से हुये हैं। मंत्रालय के इस हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवन्त सिन्हा, अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा संलग्न किये गये दस्तावेज लड़ाकू विमानों की युद्धक क्षमता से संबंधित हैं और इन्हें बड़े स्तर पर वितरित किया गया तथा यह देश के दुश्मन तथा विरोधियों के पास भी उपलब्ध हैं। रक्षा सचिव संजय मित्रा द्वारा दाखिल इस हलफनामे में कहा गया है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। केन्द्र सरकार की सहमति, अनुमति या सम्मति के बगैर वे जिन्होंने इन संवेदनशील दस्तावेजों की फोटो प्रतियां करने और इन्हें पुनर्विचार याचिकाओं के साथ संलग्न करने की साजिश रची है और ऐसा करके ऐसे दस्तावेजों की अनधिकृत तरीके से फोटो प्रति बनाकर चोरी की है, ने देश की सार्वभौमिकता, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्तों को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित किया है।

यह हलफनामा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने छह मार्च को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आरोप लगाया था कि पुनर्विचार याचिका उन दस्तावेजों पर आधारित है, जो रक्षा मंत्रालय से चुराये गये हैं। वेणुगोपाल ने दो दिन बाद दावा किया कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी नहीं किये गये थे, बल्कि शीर्ष अदालत में उनके कहने का तात्पर्य यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में मूल की फोटोप्रतियां इस्तेमाल की हैं, जिन्हें सरकार गोपनीय मानती है। हलफनामे में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस और दूसरों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के संबंध में हुये केन्द्र के विभिन्न समझौतों में गोपनीयता परिकल्पित थी। इसमें कहा गया है कि यद्यपि केन्द्र गोपनीयता बना कर रखता है, सिन्हा, शौरी और भूषण संलग्न किये गये दस्तावेजों को आधार बना रहे हैं और वे संवेदनशील जानकारी लीक (शेष पृष्ठ 10 पर)

भारतीयों में रोजगार के लिये जरूरी कौशल नहीं

डिग्री से इतर शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत

लाखों इंजीनियर व बिजनेस डिग्री वाले तीन चौथाई युवा रोजगार के काबिल नहीं

मुंबई। दुनिया की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम की प्रमुख गिन्नी रोमेटी ने कहा है कि भारतीयों के पास जरूरी कौशल का अभाव है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ नये जमाने के रोजगार अधिक मात्रा में सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सभी को डिग्री से इतर शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत पर जोर दिया।

कुल 180 अरब डॉलर के घरेलू साफ्टवेयर उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आईबीएम की चेयरमैन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी रोमेटी ने कहा कि यह वैश्विक समस्या है और केवल भारत तक सीमित नहीं है। कंपनी के एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने बुधवार को कहा कि भारत में भी वहीं मुद्दे हैं। रोजगार सृजित हो रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक काबिलियत या कौशल नहीं है। रोमेटी ने कहा, आपको यह भरोसा करना होगा कि डिग्री के मुकाबले कौशल ज्यादा जरूरी है।

उन्होंने यह बात ऐसे समय कही है, जबकि बताया जाता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री वाले लाखों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। उन्हें अगर शुरुआती स्तर पर नौकरी मिलती भी है तो अनुभव रखने वाले अर्द्धकुशल कामगारों से बहुत कम मेहनताना मिलता है। ऐसी खबरें हैं कि लाखों इंजीनियरों तथा बिजनेस स्कूल से डिग्री लेने वाले युवाओं में करीब तीन चौथाई रोजगार के काबिल नहीं हैं। यह देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ दाखिला प्रक्रिया की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है।

निजी आर्थिक शोध संस्थान सीएमआईई के आंकड़े में कहा गया है कि फरवरी की स्थिति के अनुसार 3.12 करोड़ युवा पूरी सक्रियता के साथ रोजगार तलाश रहे हैं। कुल 1.35 करोड़ की आबादी में 60 प्रतिशत से अधिक 35 साल से कम के हैं। उन्होंने कहा कि धारणा के विपरीत पर्याप्त मात्रा में रोजगार हैं और उतनी ही संख्या में युवा नौकरी खोज रहे हैं, लेकिन कौशल की कमी रोड़ा है और यह एक वास्तविक समस्या है। रोमेटी ने कहा कि कंपनियों तथा सरकार को इस मसले के हल के लिये मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी दुनिया नहीं चाहेंगे जहां कुछ लोग नई प्रौद्योगिकी में काम करना जानते हैं, जबकि बहुसंख्यकों के साथ ऐसा नहीं है।

जज ने हार्दिक के मामले से खुद को अलग किया

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बुधवार को पाटीदार समुदाय के नेता हार्दिक पटेल की उस अर्जी पर सुनवायी से स्वयं को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने 2015 के दंगा मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है। 25 वर्षीय पटेल मंगलवार को गांधीनगर में आयोजित कांग्रेस की रैली में पार्टी में शामिल हुए थे और उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जतायी थी। न्यायमूर्ति आरपी धोलारिया ने स्वयं को सुनवायी से अलग करते हुए कहा, मेरे समक्ष नहीं। गत वर्ष जुलाई में एक सत्र अदालत ने पटेल को 2015 में विसनगर में दंगा और आगजनी के लिए दो वर्ष की सजा सुनायी थी, जब पाटीदार आरक्षण आंदोलन राज्य में गति पकड़ रहा था। मेहसाणा जिले के विसनगर की अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने की वजह से हार्दिक पटेल उच्चतम न्यायालय की एक व्यवस्था के आलोक में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। हार्दिक पटेल ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुये उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने यद्यपि गत वर्ष अगस्त में पटेल को जमानत प्रदान करने के साथ ही उनकी दो वर्ष की सजा निलंबित कर दी थी, लेकिन उसने उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगायी थी।

गंगा जल की गुणवत्ता होगी सार्वजनिक

एनजीटी का उत्तराखंड व यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश

मासिक आधार पर बताना होगा पानी नहाने और पीने योग्य है या नहीं

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर गंगा जल की गुणवत्ता मासिक आधार पर सार्वजनिक करने के साथ ही यह बताने को भी कहा है कि पानी नहाने और पीने योग्य है या नहीं। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली एक पीठ ने आगाह किया कि ऐसा करने में विफल रहने पर दोनों राज्यों के प्रदूषण बोर्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अधिकरण ने इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को उसके उस हलफनामे को लेकर आड़े हाथ लिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने कानपुर से बक्सर (द्वितीय चरण) और बक्सर से गंगा सागर (तृतीय चरण) के हिस्से के लिए प्रासंगिक सूचना मुहैया नहीं करायी है।

अधिकरण ने कहा कि एनएमसीजी की ओर से दायर हलफनामा एक निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। उसने कहा, यह संकेत दिया गया है कि राज्यों ने सूचना मुहैया नहीं करायी है और इसलिए कार्ययोजना निर्धारित समयसीमा के भीतर तैयार नहीं की जा सकी। एनएमसीजी का निरुत्साही रुख समझ से परे है, क्योंकि सरकार ने उसका गठन गंगा के कायाकल्प के लिए किया है तथा उसका संचालन एवं राज्यों के साथ समन्वय को गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश 2016 में निर्दिष्ट किया गया है।

अधिकरण ने कहा कि एनएमसीजी और राज्य सरकारों की ओर से कार्ययोजना दायर करने में देरी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि गंगा को एक राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अधिकरण ने कहा, हमें जवाब नहीं देना और चरण दो और चरण तीन के लिए कार्ययोजना तैयार करने में असफल रहने के लिए सख्त कार्रवाई करनी पड़ सकती है। इसमें यह भी शामिल है कि एनएमसीजी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल द्वारा पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ सकता है। अधिकरण ने कहा, हम एनएमसीजी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों को तदनुसार कदम उठाने का अंतिम मौका देते हैं। यह अधिकतम सात दिन के भीतर होना चाहिए और कार्ययोजना 30 अप्रैल तक दाखिल की जानी चाहिए।

स्वच्छ सर्वेक्षण में शहरों की रैंकिंग में कई खामियां

नयी दिल्ली। पर्यावरण क्षेत्र के थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरॉमेंट ने दावा किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 और शहरों की रैंकिंग में कई खामियां थीं।

सीएसई ने दावा किया कि सर्वे के लिए जमीनी स्तर पर आकलन महज 28 दिनों में पूरा कर लिया गया, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वे के नतीजे आम चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले घोषित कर दिए जाएं। संगठन ने कहा कि 2018 में यह कवायद 66 दिनों से अधिक समय में पूरी हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते छह मार्च को यहां एक कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड दिए थे, जिसमें इंदौर को लगातार तीसरे साल भारत के सबसे साफ-सुथरे शहर का अवॉर्ड मिला। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर और कर्नाटक का मैसूर इस श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। सीएसई ने यह भी कहा कि सर्वे में डेटा जुटाने और पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों, पात्रता प्राप्त सर्वेक्षकों और प्रमाण-पत्र देने वालों को शामिल नहीं किया गया था। संगठन ने कहा कि कई राज्यों के शहरी विकास विभाग और शहरों के प्रशासकों ने सर्वेक्षकों की अक्षमता के बारे में अपनी चिंता जाहिर की थी।

डर के माहौल में आर्थिक वृद्धि संभव नहीं

कांग्रेस देश के मिजाज को बदलेगी, लोग खुश व सशक्त महसूस करेंगे : राहुल

- रॉबर्ट वाड्रा की जांच करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जांच हो
- राफेल सौदे में प्रधानमंत्री ने की समानांतर बातचीत
- सभी संस्थानों को नागपुर से संचालित करना चाहती है भाजपा

चेन्नई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि आर्थिक वृद्धि सीधे-सीधे देश के मिजाज से जुड़ी है और नकारात्मक व डर के माहौल में आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते।

एक कॉलेज में छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के मिजाज को बदल देगी और लोगों को खुश एवं सशक्त महसूस कराएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने छात्राओं से कहा कि वे उन्हें राहुल कहकर पुकारें। अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, न कि चुनिंदा तरीके से। छात्रों के साथ अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने राफेल सौदे का मुद्दा भी उठाया और विमान की कीमतों एवं खरीद प्रक्रिया को लेकर अपने आरोप दोहराए। गांधी ने कहा, मैं यह कहने वाला पहला शख्स होऊंगा, रॉबर्ट वाड्रा की जांच करें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जांच करें।

एक सवाल के जवाब में राहुल ने आरोप लगाए कि मोदी एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने बातचीत की अनदेखी की और राफेल सौदे में समानांतर बातचीत की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री में मीडिया का सामना करने का साहस होना चाहिए और पूछा कि मोदी क्यों छिप रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का इरादा देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लेना और उन्हें संघ के मुख्यालय नागपुर से संचालित करना है। गांधी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगी। इस बयान पर उत्साह में आई भीड़ के समक्ष उन्होंने कहा कि नेतृत्व वाली जगहों पर पर्याप्त महिलाएं नहीं दिखती हैं। आप सत्ता में महिलाओं को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उनके प्रति नजरिए में बदलाव नहीं आता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें अपनी मां सोनिया गांधी से प्रेम एवं विनम्रता की सीख मिली है। गांधी ने छात्राओं से पूछा, क्या आपको नोटबंदी पसंद आई? जब छात्राओं ने 'न' में जवाब दिया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि नोटबंदी ने जो नुकसान किया है, वह काफी साफ है। प्रधानमंत्री को आपसे सलाह लेनी चाहिए थी। गांधी ने छात्राओं से कहा कि वे उन्हें चुनौती दें और असहज करके दिखाएं। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी भीड़ के बीच खड़े होकर लोगों के सवालों का जवाब दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मोदी की नीतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे जम्मू कश्मीर जल रहा है। उन्होंने केंद्र पर आतंकवाद को रणनीतिक और व्यवस्थित तरीके से नहीं संभालने का आरोप लगाया जैसे ही मोदी ने सत्ता संभाली, उन्होंने (शेष पृष्ठ 10 पर)

प्रधानमंत्री गुस्से में थे, मैंने थोड़ा स्नेह जताया

चेन्नई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह नरेन्द्र मोदी से वास्तव में प्रेम करते हैं। इसीलिए जब उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री को बेहद गुस्से में देखा तो उन्हें गले लगाकर अपने प्रेम को जताने का प्रयास किया था। गांधी ने उस घटना को याद किया, जब उन्होंने मोदी को गले लगाया था। उन्होंने कहा कि वह मोदी से घृणा नहीं कर सकते क्योंकि प्रेम देश, हर धर्म और लोगों की नसों में भरा हुआ है। जब एक छात्रा ने उनसे यह पूछा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को गले क्यों लगाया, तो गांधी ने कहा कि संसद में मोदी जब उनकी पार्टी कांग्रेस, उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी पर हमला बोल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मोदी काफी गुस्से में थे। उन्हें भीतर से मोदी के प्रति स्नेह उभरा और उन्हें गले लगाया।